लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1296

11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आईपीडीएस के अंतर्गत वस्त्र प्रसंस्करण परियोजनाएं

1296. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) के अंतर्गत स्वीकृत नए प्रसंस्करण पार्कों और मौजूदा वस्त्र प्रसंस्करण परियोजनाओं तथा प्राप्त लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि सहित इन परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के संदर्भ में आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से अपशिष्टों के प्रबंधन और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए और मौजूदा दोनों क्लस्टरों में आईपीडीएस के अंतर्गत कौन-सी प्रौद्योगिकियां क्रियान्वित की गई हैं;

(घ) क्या आईपीडीएस के अंतर्गत विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से कोई प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई देरी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ): वस्त्र उद्योग को आवश्यक पर्यावरण मानकों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने और प्रसंस्करण क्लस्टरों/प्रसंस्करण पार्कों में नए सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी)/सीईटीपी के उन्नयन का समर्थन करने के लिए, सरकार 2013 से एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल प्रसंस्करण मानकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारतीय वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सुविधा प्रदान करना है। यह योजना मौजूदा वस्त्र क्लस्टरों में प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता वृद्धि के लिए भी लागू होगी। यह योजना 31.03.2021 तक कार्यान्वित थी। अब, यह योजना केवल चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है। योजना के तहत, 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जो वर्तमान में कार्यान्वयन में हैं। प्रौद्योगिकी सहित भौतिक और वित्तीय प्रगति की कार्यान्वित की जा रही परियोजनावार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

संविदात्मक संबंधी विवादों और भूमि आवंटन से संबंधित मुद्दों के कारण कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हुई है।

आईपीडीएस के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में किसी भी परियोजना की स्थापना के लिए मंत्रालय में कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

अनुबंध

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	प्रौद्योगिकी	प्रस्तावित इकाइयों की संख्या	यूनिट कनेक्टेड	कुल स्वीकृत परियोजना लागत	भारत सरकार का स्वीकृत हिस्सा	भारत सरकार का जारी कुल हिस्सा
1	बालोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार एवं रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान	2015	मौजूदा और पूरक जेडएलडी (यूएफ/आरओ प्रणाली) का उन्नयन + आरओ रिजेक्ट (रिजेक्ट मैनेजमेंट) के लिए सौर वाष्पीकरण + एमईई	400	400	131.89	65.89	49.46
2	जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार एवं रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान	2015	मौजूदा और पूरक जेडएलडी-जेडएलडी (यूएफ/आरओ प्रणाली) का उन्नयन + आरओ रिजेक्ट (रिजेक्ट मैनेजमेंट) के लिए सौर वाष्पीकरण +एमईई	111	111	38.50	19.25	14.43
3	सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, राजस्थान	2016	प्राइमरी ट्रीटमेंट, रासायनिक-जैविक आईएफ+आरओ+थर्मल ट्रीटमेंट (एमवीई)	775	192	159.00	75.00	37.5
4	नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क, राजस्थान	2021	आरओ, एमईई और एटीएफडी के साथ मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर (एमबीआर)	15	15	129.42	64.71	6.30
5	पाली कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, राजस्थान	2016	जेडएलडी-यूएफ+आरओ+थर्मल ट्रीटमेंट में उन्नयन	400	400	100.00	50.00	37.50
6	गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क, गुजरात	2018	मौजूदा सीईटीपी उन्नयन+यूएफ+आरओ +एमवीआरई	38	33	146.39	73.195	54.84
कुल						**705.2**	**348.045**	**200.03**

***